RAJYA SABHA

[illegible] the 4th August 1992/[illegible]
[illegible] 1914 (Saka

[illegible] met at [illegible] o'clock.

The Deputy [illegible] Chair.

[illegible]

[illegible] एस०टी०डी०—पी०सी०ओ०

[illegible] : [illegible] कृपा करेंगे कि [illegible]

[illegible] अंत तक देश में [illegible]

[illegible] क्या यह सच है कि इसी संख्या [illegible] एस०टी०डी०/पी०सी०ओ० लगाने के [illegible] पर अतिरिक्त भार [illegible] प्रतिबंध [illegible] विचार [illegible]

THE DEPUTY MINISTER (SHRI [illegible] NAIDU) OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI [illegible] RANGAYYA NAIDU): Sir, the number of ISD/STD [illegible] Public Telephones in the [illegible] on 31st May, 1992 was 25,14[illegible]

(b) ISD/STD [illegible] Public Telephones are [illegible] to public and are very popular. As a result a large amount of traffic is [illegible] generated especially during night hours and this gives rise to overloading/congestion particularly in the case of small capacity systems/exchanges. Department is taking action to augment the circuits to the trunk automatic exchanges to overcome this problem.

श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : उपसभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एस०टी०डी०/पी०सी०ओ० व्यक्तिगत लोगों को देने के उद्देश्य में उन्होंने कहा था कि यह बेकारों को दिया जाएगा तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक एस०टी०डी०/पी०सी०ओ० लगाने का औसतन व्यय क्या आता है ?

संचार संराज्य के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) मैडम, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि हिसाब से आप एस०टी०डी०/पी०सी०ओ० दे रहे हो जो मुझे महसूस हुआ । मैडम पहले इसकी सैंक्शन हुआ करती थी डिस्क्रीशन पावर से, जब हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले हमने यह किया कि अगर पब्लिक को हम पर्सनल टेलीफोन्स न दे सकें तो पब्लिक टेलिफोन्स इतने करें कि लोगों को [illegible] इसलिए हमने इस पालिसी को [illegible] किया । पहले इसमें कई कैटेगरीज रखी थीं और बहुत कम पी०सी०ओ० दे पाते थे । हमने यह किया कि जो भी कई बेरोजगार हों उनमें हमने सभी को इनक्लूड किया चाहे वह कैंडीडेट हो एस०टी० [illegible] हो सबको जो भी मांगे उसको दो । तो उससे एक फायदा हुआ कि अब तक 25 हजार टेलीफोंस जैसाकि पत्रक में कहा गया है दीजिए लगे । इसमें से लगभग 10 हजार एस०टी०डी०/पी०सी०ओज० इसी साल 1991-92 में लगे और इस साल का टार्गेट हमने 20 हजार का रखा । आप कभी भी नेशनल हायवे और मैन रोड पर जाएं तो ज्यादातर आपको बोर्ड दिखायी देंगे कि एस०टी०डी०/पी०सी०ओ० आप यहां दो टेलीफोन काल कर सकते हैं । मकसद सरकार का यह था कि टेलीफोन की सुविधा जल्दी-से-जल्दी और ज्यादा-से-ज्यादा मात्रा में हमारे नागरिकों तक पहुंच सके । लिबरलाइजेशन का यह फायदा हुआ कि थोड़ी-बहुत उसमें जो कुछ खामियां थीं कहीं ऐसा होता था कि थोड़ी-बहुत सेवा की जाए तब यह एस०टी०डी० / पी०सी०ओ० मिले वह भी खत्म हो गयी क्योंकि हमने खुली बात कर दी कि कोई भी आए उसको पी०सी०ओ० देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को । अगर नहीं दे रहे हैं तो उसका रीजन देना पड़ेगा कि यह लाइन एवलेबल नहीं है । तो इसमें थोड़ी सी डिपार्टमेंट में भी सफायी आयी और लोगों तक सुविधा भी ज्यादा मात्रा में पहुंची जोकि हमारी सरकार का उद्देश्य था ।

उपसभापति : सैकंड सप्लीमेंटरी ।

श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : उपसभापति महोदया, मेरे असली प्रश्न का उत्तर न दिया गया । मैंने यह पूछा कि एक पी०सी०

ओ० लगाने में स्थापना व्यय क्या आता है, मंत्रीजी यह बताएं ?

श्री राजेश पायलट : मैडम एक टेलिफोन लाइन पी०सी०ओ० या पर्सनल लाइन का कास्ट में उसकी जगह-जगह फर्क [illegible] है। एवरेज जो मुझे दिल्ली का हिसाब बताया है उसमें करीबन 30 हजार रुपए एक लाइन पर सरकार का खर्चा आ जाता है जब कहीं टेलीफोन दिया जाए। [illegible] किस जगह के लिए माननीय सदस्य पूछना चाह रहे हैं उस जगह के [illegible] कितना खर्चा आएगा उसके लिए मैं अलग से माननीय सदस्य को इनफार्म कर दूंगा।

श्री प्रमोद महाजन : वैरोजगारों को आप दे रहे हैं वह यह जानना चाहते हैं ?

उपसभापति : जिन्हें मैंने अभी इजाजत नहीं दी है अगर वह सप्लीमेंटरी न करें मेहरानी होगी।

श्री राजेश पायलट : अगर वह पूछना चाहते हैं तो उपसभापति महोदया मैं जवाब दे रहा हूं। रुपए 9600 सेक्यूरिटी के जमा करने पड़ते हैं जो भी भाई और हमारे नागरिक भाई पी०सी०ओ० लेना चाहें। वह इसलिए कि उनको 20 परसेंट का कमीशन है जिसका 6 महीने का ऑन द एवरेज 1600 रुपए इन्होंने निकाला। शुरू में तो 9600 रुपए की सेक्यूरिटी जमा करनी पड़ती है सिर्फ यही एक खर्चा नागरिक को उठाना पड़ता है एस०टी०डी०/पी०सी०ओ० लेने के लिए 6 महीने के बाद सिक्युरीटी डिपाजिट का पुर्ननिधार्ण होता है पी०सी० ओ० की एवरेज मन्थली कालिंग रेट के आधार पर।

श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : मैडम, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है . .

उपसभापति : यह दूसरा आपका हो गया। . . (व्यवधान)

श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : नहीं। . . . (व्यवधान) . . .

उपसभापति : आपका कनेक्शन जुड़ा नहीं था।

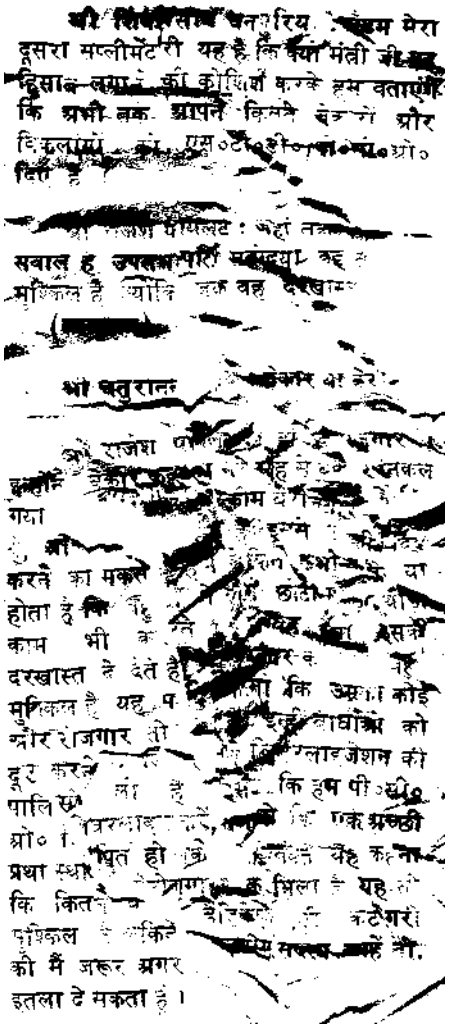

SHRI P. UPENDRA: Minister ;aid that priority is being giver to the handicapped and the unemploye youth, but my information is that a larg number of applications from these cate-y. gories are pending with the Ministry and the Department at various levels. Can he give figures of the pending applications from the handicapped and the unemployed persons now?

THE DEPUTY CHAIRMAN: He said that he will give.

SHRI P. UPENDRA: Part (b) of my question is, they are being insisted on fix-

ing time-metering machines which are very cosily. For some people who take a little loan and set up these things, it is very difficult. It is good from the public interest point of view because they will not cheat the public, but it is very difficult to provide them. We have received a number of representations from these categories. Will he consider at least pending these machines on hire or charging them a nominal fee or impressing upon the banks to give loans for these machines?

THE DEPUTY, CHAIRMAN: A time-metering machine for asking questions and replying them in the House, is also needed.

SHRI RAJESH PILOT: Madam, as far as the question of categories is concerned, I have said earlier in reply to the first supplementary that this category was prevailing and seriously speaking, I had received complains'- that on a handicapped category some other gentlemen had been misusing the facility. That is why we liberalised i*. When you liberalise any policy, then having a priority '-leomes very difficult. When I say it is available for everyone, it is very difficult to monitor at any level to see whether he is a hanjiipapwsd or not, but I havve not received many complaints about handicapped persons having been denied. Intemaly we have said that if there are two gentlemen waiting in the same line, please give priority to the handicapped or the unemployed. This understanding we have in the Department.

Coming to part (b) of the supplementary. the hon. Member has said that it is very costly to have a charging machine. There- has to be some system whereby individual citizen is not charged more and this is costing varying from Rs. 4000 to Rs. 50000. Banks are giving loans. Anybody who wants to take loan, banks are giving loans and, frankly speaking, 'the income from this is also very handsome. They save from Rs. 2000 to Rs. 50,000 per month in some cases. In Gujarat we have received representations when I was there. I asked one of the subscribers, "Youngman, how much do you earn?" He said that in Gujarat on an average it is round about Rs. 25,000 to Rs. 30,000 per STD PCO. Sometimes, you find lines in the night carrying international calls. So, it is a very good scheme. It is giving a lot of revenue to us also. There is a lot of healthy competition coming up. So, let us keep the liberalisation on so that there is no corruption and there is a healthy competition among the subscribers to give a better service.

SHRI HIPHEI: Whenever STD call is made pertaining to the North East in India, the answer on the computer is, "All lines on this route are busy. Try after some time". Even after five minutes if we make a call, the same answer comes. So, we have to book a trunk call. But the problem with the trunk call is that after the talk is over the line is not disconnected and we have to pay for the line that we have not used. Will the Minister take some remedial measures to solve this problem?

SHRI RAJESH PILOT: Madam, he is very right that the north-east is one of the sectors which require priority. The terain and other things in that area are very difficult, and that is why our Department has established a special task force for the- north-east and we are giving priority for more eiectronics and automatization in the north-east. It is a problem in some of the areas where it is very difficult for trunk calls to get through. I am aware of it and we are putting full pressure to get the system moving.

श्री माहेश्वर सिंह : उपसभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो एस०टी०डी०/पी०सी० ओ० की स्वीकृति दी जाती है वह किस स्तर पर दी जा रही है, क्या मापदंड है और क्या स्वीकृति देते समय इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि उस एक्सचेंज की कैपेसिटी क्या है ? सरकार के पास कितने केसिस ऐसे आए हैं जहा ओवर लोडिंग की वजह से समस्या उत्पन्न हुई है और आर्गुमेंटेशन विचाराधीन है ?

श्री राजेश पायलट : मैडम, यह बात सही है कि जब शुरू में स्वीकृति की

प्रथा थी तो डी०जी० लेवल के आफिसर वह स्वीकृति देते थे । हमें बहुत देर लगी इस बात का प्रचार करने में कि इसकी स्वीकृति अब खुल गई है, जो भी एप्लाई करेगा, उसको मिलेगी । सारी अखबारों में, टेलीविजन में, रेडियो पर हमने खूब सारे देश में प्रचार किया कि इसके लिए आप कहीं दौडे नहीं, सीधे जाएं और कहें कि मुझे एस०टी०डी०/पी०सी० ओ० फलां जगह चाहिए । हमने यह भी आदेश दिए कि 5 प्रतिशत, टेलीफोन एक्सचेंज की कैपेसिटी एस०टी० डी०/पी०सी०ओ० के लिए रिजर्व रखें जिससे कि जितनी कैपेसिटी आफ कनेक्टिविटी हो, उसमें से 5 प्रतिशत इनके लिए हो सके । मैं यह बात अब भी मानने के लिए तैयार हूं कि अब भी जब हमारे नौजवान भाई जाते हैं अफसरों के पास, अधिकारियों के पास तो उतनी खुली अभी बात नहीं है कि आए और उनको दे दी, लेकिन हम इसमें सुधार की कोशिश कर रहे हैं । हमने हर सी०जी० एम० को निर्देश दिए हैं कि आप इसको मोनिटर करें लेकिन कुछ वास्तविकता ऐसी है कि जब कुछ थोड़ी-बहुत आमदनी ज्यादा लगे तो लोग उसमें थोड़ी बहुत एटरेक्शन पैदा कर देते हैं । पंजाब के बड़े केस ऐसे आए—लुधियाना से जालंधर से, जहां-जहां ज्यादा इंटरनेशनल कालस होती हैं वहां-वहां उसमें थोड़ा सा, लोग आगे बढ़कर कुछ थोड़ा बहुत स्वास्थ्य खराब करने की आदतें डाल देते हैं, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन हमने इतना प्रचार सारे में कर रखा है कि यह गवर्नमेंट की लिबरलाइज पालिसी है कि जो भी नागरिक मांगे, उसको एस०टी०डी० पी०सी०ओ० दिया जाए, नहीं दिया जाए तो जवाब दिया जाए कि क्यो नहीं दिया जाए। लेकिन अभी भी प्रचार उसका उतना नहीं है जितना माननीय सदस्य ने समझा है ।

उपसभापति : श्री डेविड लेजर ।

श्री माहेश्वर सिंह : मैडम, मेरा जवाब नहीं आया ।

उपसभापति : श्री डेविड लेजर । अभी जवाब नहीं आया? . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री माहेश्वर सिंह : मैडम, मैंने यह जानना चाहा था . . . ।

उपसभापति : प्लीज । अभी आप बोल . . . **(व्यवधान)** . . . प्लीज ।

श्री माहेश्वर सिंह : मैंने यह जानना चाहा था कि जब आप यह स्वीकृति देते है तो क्या इसमें एक्सचेंज की कैपेसिटी को भी ध्यान में रखा जाता है और जो . . . **(व्यवधान)** . . . एक्सचेंज ओवर लोडिड चल रही है, उसका क्या कारण है ?

उपसभापति : वह इन्होंने पहले सवाल में दिया है । He has already given. . . *(Interruptions)* . .

श्री राजेश पायलट : मैडम, मैंने कहा . . . **(व्यवधान)** . . . माननीय सदस्य यह जानना चाह रहे थे कि यह जब एस०टी० डी०/पी०सी०ओ० देते हैं तो एक्सचेंज की कैपेसिटी को ध्यान में रखा जाता है या नहीं रखा जाता है ? मैंने खुद कहा कि अगर क्षमता है तो मिलेगी, चाहे एस०टी० डी०/पी०सी०ओ० लें या पर्सनल लाइन लें । लाइन के लिए तार तो एक ही जाएगा चाहे उस पर एस०टी०डी०/पी०सी० ओ० लगायें या पर्सनल टेलीफोन लगायें । तो अगर क्षमता नहीं होगी तो एस०टी०डी०/ पी०सी०ओ० भी नहीं मिलेगी और पर्सनल लाइन भी नहीं मिलेगी । इसलिए मैंने कहा कि लिबरलाइज है, क्षमता है मिलेगी, क्षमता नहीं है तो लिखकर देंगे कि क्षमता नहीं है, आपकी दरख्वास्त ले ली, जैसे ही क्षमता बढ़ेगी आपको दे देंगे ।

SHRI DAVID LEDGER: *Madam,* when we talk of efficiency or Inefficiency of the Telecommunications system, the first thing that comes to mind is the faulty billing system of the Department. The hon. Minister is perhaps aware of the fact that a number of faulty bills have been served on subscribers—even MPs have not been spared.

AN HON. MEMBER: Why should Members be spared?'

SHRI DAVID LEDGER: I do not say that Members should be spared. MPs also have been victims of this malpractice. Madam, I was also a victim, along with a number of MPs. 'We were served bills whcih were not correct, and we demanded detailed statements from the Department. These statements have not come to us as yet. Our salaries and allowances were deducted. We wrote to the Minister. I personally wrote to the Minister and, mercifully, the deduction was stopped. But I am told that they are going to start it all' over again and this time they are not going to deduct the full salary but only half the salary. Even if this is done, it is going to be a grave injustice. The newspapers are full of reports. Even today's newspaper has a write-up on this. So I would like to request the Minister to give an assurance to us in this House that he will institute a thorough inouiry into these malpractices and also assure us that subscribers are not put to such inconvenience in future and MPs, in particular, are not harassed.

SHRI RAJESH PILOT; *It* is a fact. There are two types of complaints on the billing. Om is wrong billing and another Where call is made on some other number and the bill is on some other number. These are the two complaints which carme to my notice. As far as the billing is concerned, the Government has taken a decision that whenever a wrong bill comes, you take a provisional bills based on average for your last 6 months bill and deposit the amount. In such a situation your telephone will never be disconnected. Every two months there will be a cotnmittee sitting in a paritcular district or division, which will go into the dispute whether it is right or wrong, and will come up with a statement that these calls were made by so and so at So and se time. The second point was where the call is made from some number and the bill is put on some other number. It is a fact that there are a lot of such problems in Bombay, Calcutta and Delhi. In such cases revenue leakages are also there. There were complaints that you may call anywhere; you just pay Rs; 1,000/- per months. There were some complaints against such sta. We immediately took a decision and handed over the whole functioning of the Department to the CBI. We have caught some people in Bombay. There is a lot of improvement and revenue is now coming up. We have registered those cases with the Police and action is being taken. - The point is that the revenue leakage is a national loss. It is a national loss and it is a burden on some individuals. So, on both sides we have taken decisions. My only problem is that publicity is not given to all these decis'ons, like the decision of provisional bill taking six months average Bill you pay. Not many people know about it. When they go to Office, the clerk there really does not take action. So, the common citizen is harassed. I am trying to improve the channels and most probably it will be written on every Exchange and every Accounts Officer will ensure that these rules are adopted.

उपसभापति : मंत्री जी, यह बात जिन लोगों के साथ है, आप सब को चिट्ठी लिखकर भिजवा दें।

SHRI RAJESH PILOT: About the MPs, let me tell you I have requested my friends, Shri Sahu, Shri Bhuvnesh Chaturvedi and Shri Sharad Digbe to sit together, get all such disputed bills from the hon. Members. I will personally look into them with the help of this Committee.

Request for Constitution of Fifth Pay Commission

*382. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have been requested to constitute the Fifth Pay Commission to make further revision of pay scales of Government employees in view of rising prices of daily use items;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether any action on these requests have since been taken; and

(d) if so, details thereof and if not, what are the reasons therefor?